the field of ship building, repair and allied activities;

(b) if so, what is the reaction of Government in this regard;

(c) by when the private sector will be allowed entry into ship industry; and

(d) to what extent the problems being faced at ports would be eased?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Private sector is already being allowed in ship building, repair and allied activities. Privatisation in these fields would not affect the working or the problems of the ports since the ports at present do not undertake any of the activities as mentioned in part (a) of the question.

Conversion of Delhi-Bombay National Highway as National Expressway

1717. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision to include Delhi-Jaipur-Ahmedabad-Bombay National Highway in National Expressway system;

(b) whether under the proposed Expressway System Delhi-Jaipur stretch has been accorded top priority, keeping in view the heavy traffic and accidents on this route; and

(c) if not, the reasons therefor and what are the other details of expenditure etc. likely to be involved and share of Government of Rajasthan, if any?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Sir.

(b) and (c) There is no approved Expressway System for the country at present.

Completion of road between Panaji and Belgaum

1718. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of non-completion of road between Panaji and Belgaum via Anmod in view of non-availability of fund from Central Road Fund;

(b) whether it is a fact that this new road will cut short distance between Panaji and Belgaum by 30 Kms and save costly fuel; and

(c) if so, what steps are being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) Yes, Sir. The State Government has forwarded a proposal for improvement of Belgaum-Jamboti-Kanakambi-Chorla-Goa Road estimated to cost Rs. 75 lakhs for being financed out of the Central Road Fund However, this proposal could not be processed for sanction since actual augmentation of the Central Road Fund as per the revised Resolution adopted by Parliament on 13-5-1988 is yet to take place.

दिल्ली परिवहन निगम के अधीन संचालित प्राइवेट बसों के कर्मचारियों का व्यवहार

1719. **श्री राम नरेश यादव :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 25 नवम्बर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 247 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के अधीन संचालित प्राइवेट बसों के कर्मचारी यात्रियों के साथ बहुत ही अशिष्ट और अपमान-जनक व्यवहार करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके व्यवहार में सुधार लाने के लिए प्राइवेट बस मालिकों को क्या सुझाव दिये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) ऐसे कुछ मामले दिल्ली परिवहन निगम/सरकार के ध्यान में आये हैं । निजी प्रचालकों की बसों के ड्राइवरों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार को, दिल्ली परिवहन निगम और निजी प्रचालकों के बीच हुए समझौते में, चूकों/गलतियों का एक हिस्सा बना दिया गया है । शिकायतें प्राप्त होने पर जहां आवश्यक होता है, निजी प्रचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं तथा उन पर दंड/जुर्माने लगाए जाते हैं। निगम ने निजी बस प्रचालन को जांच आदि के माध्यम से नियमित करने के लिये एक तंत्र का गठन किया है जो एक वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा । ये जांच स्वतंत्र रूप से अथवा यातायात पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की जाती है ।

Allocation of Fund to handloom sector in Tamil Nadu

@1720. SHRI R. T. GOPALAN: Will the Minister of State for TEXTILES be pleased to state:

(a) What allocations have been made by the Central Government for the development of handloom sector in Tamil Nadu during the year 1990-91; and

(b) what are the details of the plan for the year 1992-93?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) and (b) Allocation of funds to the handloom sector is made scheme-wise and not state-wise on the basis of proposals/schemes received from the State Governments. During 1990-91, a sum of Rs. 3624.64 lakhs was released to the State of Tamil Nadu for the schemes in operation in the State.

कालीनों का निर्यात

@@1721. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान देश से वस्तुनिर्मित कालीन के निर्यात संबंधी स्थिति क्या है ; और

(ख) ऐसे कालीनों का किन-किन स्थानों से कितना-कितना निर्यात किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 1991 (अप्रैल–सितम्बर) के दौरान हाथ से बने ऊनी/रेशमी/संश्लिष्ट यार्न कालीनों, नमदों, दरियों आदि के निर्यात 273.05 करोड़ रुपये (अनंतिम) के हुए ।

(ख) निर्यात आंकड़े की स्थानवार मात्रा उपलब्ध नहीं है । तथापि भारत से हाथ से बने ऊनी कालीनों के कुल निर्यात में भदोही-मिर्जापुर क्षेत्र से करीब 70 प्रतिशत निर्यात हुआ और शेष निर्यात में श्रीनगर, जयपुर, आगरा आदि का योगदान रहा है ।

कालीन वित्त निगम का स्थापित किया जाना

@@@1722. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की अनुदार बैंकिंग नीति के कारण कालीन

@Previously Unstarred Question 1051, transferred from the 3rd December, 1991.

@@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1025, 3 दिसम्बर, 1991 से स्थानांतरित ।

@@@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1026, 3 दिसम्बर, 1991 से स्थानांतरित ।